अन्तरराष्ट्रीय छवि के लिए स्मार्ट सिटी

हिन्दुस्तान में स्मार्ट सिटीज विकसित करने के लिये मोदी बहुत उत्सुक हैं। अपने चुनावी भाषणों में भी मोदी ने देशवासियों को 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। उनके पास सपने दिखाने के लिये बहुत बड़ा बायोस्कोप है। लेकिन शायद उन्होंने यह न सोचा हो कि भारतीय शहरों को 'स्मार्ट सिटी' बना पाना आसान काम बिल्कुल नहीं हो सकता।

सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे ज़्यादातर पुराने शहर अनियोजित हैं, उनकी सही मैपिंग उपलब्ध नहीं है। इन शहरों की 70 से 80 फीसदी आबादी अनियोजित इलाकों में रहती है। इन इलाकों में लगातार आवाजाही होती रही है। ऐसे में आप काम की शुरूआत भी कैसे कर पायेंगे। इससे आसान तो यही होगा कि नये शहर ही बसाये जायें, जहां हर चीज़ की योजना पहले से की गयी हो। एक अन्तरराष्ट्रीय छवि तैयार करने के उद्देश्य से मोदी सरकार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम कर रही है लेकिन क्या उन्हें यह नहीं लगता कि काम करनेवाले शहर बनायें, जहां काफ़ी कुछ हो सकता हो, इसके बजाय कि उसे सिर्फ़ स्मार्ट साबित करने पर चिन्ता की जाय।

स्मार्ट सिटी 21 वीं सदी का एक शब्द है, जिसे किसी स्मार्टफ़ोन या स्मार्टहाउस की तर्ज पर सोचा गया है। लेकिन किसी शहर को स्मार्ट कहना कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि हर शहर की अपनी संस्कृति होती है, कैरेक्टर होता है। हर शहर अपने आप में काफ़ी जटिल होता है, इसलिए उसके लिए 'स्मार्ट सिटी' शब्द का प्रयोग सही नहीं लगता। स्मार्ट सिटी के सवाल पर सरकार से लेकर इन योजनाओं पर काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और आम लोग तक इस पर अलग-अलग सोच रखते हैं। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि स्मार्टनेस की परिभाषा सभी के लिए अलग होती है। अब यदि हम किसी पश्चिमी देश की ही नकल करना चाहते हैं तो वह असल में गतिशील और अनुशासित एक ऐसा शहर हो जो काम करता हो, जहां लोग साईकिल चला पाते हों, सड़कों पर पैदल चलने की जगह हो, पार्क हो, हरियाली हो, यातायात सुलझा हुआ हो, सड़कें और इमारतें योजनाबद्ध तरीके से बनी हों, शहरी और सार्वजनिक यातायात सुलभ हो। हर जगह कूड़ा फ़ैला हुआ न हो, शहर के भीतर नालों से बदबू न उठ रही हो। बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी आम सुविधाओं की अबाध आपूर्ति हो।

शहरों को सुन्दर बनना ही चाहिये। साफ़-सुथरे, सारी सुविधाओं से पूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त शहर बनने ही चाहिए। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन इसी का अगर दूसरा पहलू देखें तो, हमारे देश के करोड़ों घरों में पक्के शौचालय तक नहीं हैं। गांवों में ऐसे घरों की संख्या करीब 11 करोड़ 50 लाख है, जहां शोचालय नहीं हैं। इन घरों में शौचालय की सुविधा देने का खर्च अनुमानत: 22 खरब से 26 खरब रुपये है। शहरों का विकास तो अच्छी बात है, लेकिन गांवों की ओर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें भी साफ़-सुथरा बनाना चाहिए।

किसी भी शहर की रूपरेखा में आठ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। सुचारू एवं चुस्त-दुरुस्त सरकारी प्रशासन, ऊर्जा-पानी, बिल्डिंग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर सुविधाएं। एक शहर जो अपनी मूलभूत सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करना जानता हो, उसी के जरिए अपने नागरिकों को तमाम तरह की सुविधाएं देना जानता हो, उनकी सुविधाओं और उनके लिये अवसर मुहैया कराने के लिये केन्द्रित है, वह स्मार्ट सिटी है। लेकिन नागरिकों को इन शहरों के लायक कैसे बना पाएंगे? वे तो अपने ही ढंग से चलेंगे, नये और स्मार्ट नागरिक कहां से आएंगे? मैं अभी कनाडा के शहर वैंकूवर में हूं और यहां के प्रशासन की सक्रियता, सौजन्यता और संवेदनशीलता देख रहा हूं। प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित है उसमें अगर मगर नहीं चलता। भारत को इस तरह की प्रशासनिक सक्रियता और संवेदनशीलता की दरकार है जो सदियों से नहीं दिखाई देती। किसी भी स्मार्ट सिटी में सूचना तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर, कैमरे, वायरलैस उपकरणों, डाटा सेन्टर बनाये जाते हैं। स्मार्ट सिटी को बनाते वक्त इसे इको फ्रेंडली भी बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी में उर्जा बचाने के लिये भी पूरे इंतजाम किये जाते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर सिंगापुर ने मोदी सरकार के सामने इच्छा भी जाहिर की है। मोदी सरकार ने भारत में टियाजिन नॉलेज सिटी जैसी स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अपनी रुचि दिखायी है।

सिंगापुर के विदेश मंत्री के षणमुगम ने बताया कि मोदी स्मार्ट सिटी में पोर्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पानी के इंतजाम को लेकर काफ़ी गम्भीर हैं। षणमुगम ने मोदी सरकार को ये विश्वास दिलाया है कि सिंगापुर की तकनीक और अनुभव भारत के साथ साझा करेंगे। सिंगापुर ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के बीच 7 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करने की इच्छा जतायी है। इन स्मार्ट सिटीज में घरों से निकलनेवाले कूड़े-कचड़े को पाइपलाइन के जरिये सीधे वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जायेगा। सिटी के अन्दर ही रोज़ के काम को व्यवस्थित करने के लिए इनफॉर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन सेन्टर भी बनाया जायेगा।

असल में एक बड़ी लागत लगाकर शहर बना लेना आसान है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इसके लिये तैयार बैठी हैं। उन्हें तो लाभ कमाना है। वहीं चहेते देशी ठेकेदारों के भी बारे-न्यारे हो जायेंगे। विडम्बना यह है कि देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी योजना गुजरात में ही संकट में घिरती दिख रही है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते 2007 में गुजरात में 7,800 करोड़ रुपये के पहले स्मार्ट सिटी गिफ़्ट की नींव रखी गयी थी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट लालफीताशाही के जाल में फंसता नज़र आ रहा है।

बिल्डिंग का पूरा नहीं बनना, पावर यूटिलिटी लाइन्स का न होना और सबसे ज़्यादा अहम कॉरपोरेट की गैर मौजूदगी। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसको अमली जामा किस तरह और किन लोगों की कीमत पर पहनाया जाता है, यही असल बात है। देखते हैं कि मोदी किस तरह अपने इस ख्वाब की ताबीर पूरी कर पाते हैं।

-शैलेन्द्र चौहान

दिल्ली में पालतू कुत्तों का सम्मेलन

''मनुष्य को शेर से एक, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौए से पांच, कुत्ते से छह और गधे से तीन गुण ग्रहण करना चाहिये।''

''बहुत खाने की शक्ति रखना, न मिलने पर भी सन्तुष्ट हो जाना, खूब सोना पर तनिक आहट होने पर भी जाग जाना, स्वामिभक्ति और शूरता, ये छह गुण कुत्ते से सीखना चाहिए।''

चाणक्य

'कुत्ते! मैं तेरा खुन पी जाऊंगा।''

-धमेन्द्र, फ़िल्म शोले

कुत्ते के बारे में ऊपर जिन दो मनीषियों के उद्धरण दिये गये हैं वे तो महज बात शुरू करने का एक बहाना है। भारतीय वांग्मय में कुत्तों की महिमा का बखान भरा पड़ा है। कुत्तों पर कहावतों, मुहावरों और नीतिकथाओं की तो भरमार है ही, गालियां और वक्रोक्तियां भी कम नहीं हैं। प्राचीन काल से आज तक, भारतीय साहित्य और समाज में, कुत्तों को दुत्कार और प्रतिष्ठा दोनों ही इतनी भरपूर मिली है कि कई बार आदमी नामक प्राणी उनसे ईर्ष्या करने लगता है।

हाल ही में कुत्तों और कुत्ता पालकों को प्रतिष्ठित करनेवाली एक घटना देश की राजधानी में हुई।

दिल्ली से प्रकाशित एक नामचीन अंग्रेजी अखबार के दूसरे पन्ने पर सबसे ऊपर सात कॉलम का एक समाचार था, जिसमें तीन रंगीन चित्र बैनर हेडलाइन था। खबर में बताया गया था कि पिछले एक नवम्बर को दिल्ली हाट में कुत्तों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 5000 इन्सान, 250 कुत्ते और कुछ बिल्लियां शामिल हुईं।

दिल्ली में आयेदिन दलितों-शोषितों के सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन अखबार के किसी कोने-अन्तरे में भी उनको जगह नहीं मिलती, जबकि कुत्तों, जोंकों, सियारों और ठगों-बटमारों की बैठकें भी खबरों की सुर्खियों में रहती हैं।

बहरहाल, सम्मेलन में कुत्तों के लिये डिजाइनर पोशाक, खिलौने और नाना प्रकार के व्यंजनों की नुमाइश हुई। कुत्तों के लिये खास तौर पर बेकरी चलाने वाले भी उस सम्मेलन में शामिल हुए। उनका कहना था कि अब कुत्तों के लिए ब्रेड-बिस्कुट ही नहीं, बल्कि जन्मदिन-स्पेशल केक की मांग भी बढ रही है।

विदेशी तकनीक और विदेशी पूंजी पूजन के इस दौर में इस कुत्ता सम्मेलन में कई विदेशी नस्लों के कुत्ते भी शामिल हुए जिनमें चिहुजाहुआ और लेब्राडोर सबसे ज़्यादा आकर्षण के केन्द्र में रहे। बेचारे देसी कुत्ते अनामन्त्रित दर्शक थे।

सच पूंछें तो यह सम्मेलन कुत्ता मालिकों और कुत्ता प्रेमियों का था। कुत्ते तो हमारे घर में भी पलते थे, बची-खुची खाकर पहरेदारी करते थे। उनसे लगाव भी हो जाता था, खासकर बच्चों को। लेकिन नवउदारवादी दौर के प्रदर्शन-प्रेमी नवधनाढ्यों की तों बात ही कुछ और। उनका क्या है, वे तो अपना तोता-मैना पाले हैं। वे ही खबर बनते बनाते हैं।

-देश-विदेश

हिन्दुस्तानी अपने वतन की
सबसे छोटी अकलियत है।
उसका कोई संघ नहीं है
उसकी कोई लीग नहीं है
अपने वतन में
हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई
बहुतेरे हैं
लेकिन मैं ये सोच रहा हूं
अपने मुल्क में हिन्दुस्तानी
कितने होंगे?

-राही मासूम राजा

गतांक की चीरफ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के पिछले अंक में समकालीन मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व किसानों के हितों के मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दलों, किसान संगठनों, अण्णा हज़ारे, राजगोपाल आदि के दृष्टिकोण का 'संसद' के भीतर-बाहर राजनीतिक नूरां कुश्ती चलती रहेगी-किसान हारेगा, कार्पोरेट मारेगा' तथा 'राजगोपाल का चेहरा-अण्णा का मुखौटा' लेखों में सटीक विश्लेषण किया गया है।

भूमि अधिग्रहण कानून जो देश में अंग्रेजी सरकार के समय से चल रहा था उसे संशोधित करके 2013 में यूपीए सरकार द्वारा विपक्ष भाजपा व वाम दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम से पूंजीपति संतुष्ट नहीं हुए। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद विकास के नाम पर कारपोरेट घरानों को खुश करने के लिये 2013 के अधिनियम में संशोधन करते हुए अध्यादेश जारी कर दिया जिसे अब संसद द्वारा पारित कराकर अधिनियम बनाया जा रहा है।

सन् 2013 के अधिनियम से किसानों को जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी उसे भी समाप्त किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से मिले मुआवजे के बावजूद किसानों की बर्बादी ही होती है। किसान को भूमि से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उन्हें काश्तकारी के अतिरिक्त गुजर करने के लिये किसी अन्य व्यवसाय में महारत हासिल नहीं होती। मुआवजे में मिली राशि से वे ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं और कुछ तो विभिन्न कुव्यवसनों के शिकार भी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप कुछ समय बाद वे कर्ज़दार हो जाते हैं और कभी-कभी तो आत्महत्यातक करने को मजबूर हो जाते हैं।

सपष्ट है कि यदि बंजर भूमि अथवा बिना काश्त वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाए तो कार्पोरेट घरानों की मुनाफ़ाखोरी पर कुछ अंकुश लग पाएगा और किसान की बदहाली से किसी हद तक बचत हो पाएगी। एक अन्य तबका भूमिहीन मज़दूरों का है जिनका प्रमुख व्यवसाय खेती-बाड़ी है, परन्तु उनके पास अपनी भूमि नहीं होती और भूस्वामियों की भूमि पर मज़दूरी करते हैं तथा उनकी भूमि पर निर्भर रहते हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद उनका जीवन बसर कैसे होगा, यह किसी के एजेण्डा पर नहीं है।

लेख 'जब सत्ता ही देश को ठगने लगे तो.. !!!' में मोदी सरकार व आर एस एस द्वारा विकास के नाम पर आम जनता की बदहाली और हिन्दुत्व के प्रसार के प्रयास का उचित विवेचन किया गया है। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में जो कुछ किया था वह अब पूरे देश में किया जा रहा है। मोदी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में विकास का राग अलापते हुए कारपोरेट घरानों को सहुलियतें प्रदान करते हुए अपनी मौन स्वीकृति से संघ परिवार को समाज में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की खुली छूट दी जा रही है।

'हूडा' में व्याप्त भ्रष्टाचार का लेख 'पांच हज़ार रिश्वत न देने की कीमत तीन लाख का चूना-हूडा में पनपते -

'हूडा' में व्याप्त भ्रष्टाचार का लेख 'पांच हज़ार रिश्वत न देने की कीमत तीन लाख का चूना-हूडा में पनपते भ्रष्टाचार का एक नमूना' में पर्दाफ़ाश करने का साहस किया गया है। वास्तव में केवल 'हूडा' ही नहीं हरियाणा के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार का भयानक रोग फैला हुआ है जिसका आम जनता शिकार बनती है। लेख 'तीस्ता का जाहिरा शेख मुकाम' के जरिए गुजरात में तत्कालीन मोदी सरकार के प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था व अन्य जांच संस्थाओं का सटीक विश्लेषण किया गया है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी जिसे मोदी ने नज़रंदाज कर दिया था। मोदी व अमित शाह सभी संस्थाओं को अपने निर्देशोंनुसार कार्य करने को मज़बूर कर देते हैं। वैसे तो सत्ताधारी सभी राजनीतिक दल किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं।

लेख 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दू राष्ट्र' के ज़रिए संघ परिवार वशेषकर संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिन्दू राष्ट्र के एजेण्डे को आगे बढाने के प्रयास का प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से उचित मूल्यांकन किया गया है। लेखक का कथन कि भारत में पहली मूर्तियां बुद्ध और महाबीर की ही बनी, सत्य नहीं प्रतीत होता। वास्तव में मूर्तियां बनाने का सिलसिला सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही हो गया था। मोहनजोदड़ों तथा हड़प्पा में मातृ-देवी की अनेक पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रभावशाली विजय तथा भाजपा की शर्मनाक पराजय के संदर्भ में मोदी के घटते हुए प्रभाव का लेख 'क्या मोदी की सत्ता के पराभव का दौर शुरू हो चुका है' में उपयुक्त वर्णन किया गया है। वास्तव में लोकसभा चुनाव में भाजपा विशेषकर मोदी की विजय के बाद मोदी के करिश्में का पतन झारखंड व जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनावों के समय में ही प्रारम्भ हो गया था। लोक सभा चुनावों में भाजपा को उन राज्यों में मिली सीटों के मुकाबले में उसे वहां कम सीटें मिली थी और वह दोनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिलने से बंचित हो गई थी। कश्मीर घाटी व लद्दाख में तो उसे एक भी सीट नहीं मिली।

लेख 'हर अस्पताल चोर, डॉ. पांडे का एसियन सिरमौर इलाज का नाम, लूटमार का काम, पद्मश्री का इनाम' के जरिए एसियन अस्पताल द्वारा मरीज़ों की की जा रही लूटमार का समाचीन वर्णन किया गया है। वास्तव में सरकार तथा नेताओं के संरक्षण में यह दशा सभी निजी अस्पतालों विशेषकर सुपर स्पैशलिस्ट नाम से चल रहे अस्पतालों की है। वह समय चला गया जब निजी अस्पताल धर्माथ चलाए जाते थे। शेष प्रकाशित अन्य लेख भी उच्च स्तरीय व प्रेरणादायक हैं।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता